

मुकदमों का विवरण

बुद्धदेब साहा और ओ. आर. एस. बनाम.

पश्चिम बंगाल राज्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1692) 13 सितंबर, 2023

[जे. बी. पारदीवाला और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय ने पति और ससुराल वालों को दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए विवादित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की है। 498 ए, 304 बी को 34 आई. पी. सी. के साथ पढ़ा जाता है।

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग-जहर खाने के कारण पीड़ित-पत्नी द्वारा आत्महत्या करना-हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत के सही कारण के बारे में मौन है और विसरा रिपोर्ट में जहर पाए जाने के निशान के बारे में मौन है-अभियोजन पक्ष के मामले में प्रभाव:

आयोजित किया गया: रिकॉर्ड पर समग्र साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, किसी भी सकारात्मक विसरा रिपोर्ट के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को स्थापित करने में विफल रहा-अकेले विसरा रिपोर्ट में जहर का पता लगाने की अनुपस्थिति को इस तथ्य के निर्णायक प्रमाण के रूप में माने जाने की आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित की मौत जहर से नहीं हुई है-रिकॉर्ड पर आंतरिक साक्ष्य यह इंगित करने के लिए कि मामला जहर से आत्महत्या का है-पोस्टमॉर्टम करने वाले मेडिकल ऑफिसर का बयान कि पेट में मिलने वाली तीखी गंध वाली गंध वाली सामग्री-विशेषज्ञ का मानना ​​है कि जहर के सेवन के मामलों में, इस तरह की तीखी गंध पाई जाएगी-इसके अलावा, एफएसएल द्वारा पांच महीनों के बाद रासायनिक विश्लेषण के लिए विसरा प्राप्त किया गया था-मेडिकल ऑफिस 49834 आई. पी. सी. के साथ पठित ए, 304 बी में हस्तक्षेप नहीं किया गया। [पारस 23, 26, 27, 30, 38, 39] 333

332

बुद्धदेब साहा और ओ. आर. एस. बनाम. पश्चिम बंगाल राज्य 334

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

महाबीर मंडल बनाम बिहार राज्य [1972] 3 एस. सी. आर. 239: (1972) 1 एससीसी

748; राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1963] एस. सी. आर.

239:आकाशवाणी 1963

एससी 74-संदर्भित।

मोदीज मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, 23 वां संस्करण, संपादक:के. मथोरन और अमृत के. पटनायक; केन कुलिग एम. डी., क्रिटिकल केयर सीक्रेट्स (चौथा संस्करण) 2007 में-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 1692।

2018 के सी. आर. ए. संख्या 26 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित 23.07.2019 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

मो. अपजल अंसारी, वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।अविष्कार सिंघवी, सुश्री आस्था शर्मा, श्रेयस अवस्थी, विवेक कुमार, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

आदेश

1. यह अपील चार दोषियों के कहने पर की गई है और 23 जुलाई, 2019 को कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा 2018 की आपराधिक अपील संख्या 26 में पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दोषियों (यहां अपीलकर्ताओं) के नेतृत्व में अपील को खारिज कर दिया और इस तरह 2014 की सत्र सुनवाई संख्या 13 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दूसरी अदालत, कटवा, बर्दवान, पश्चिम बंगाल द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि और सजा के आदेश को लागू किया, जिसमें अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, "आई. पी. सी".) की धारा 498 ए, 304 बी के साथ 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। निचली अदालत ने उन्हें तीन साल के लिए कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक के लिए 5,000/- और कठोर दंड

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए सात साल की अवधि के लिए कारावास।

रोग होने का कारण:-

2. अपीलार्थी सं. 1 (बुद्धदेव साहा) अपीलार्थी सं. 2 और 3 उत्तरदाताओं का पुत्र है। अपीलार्थी नं. 4 अपीलार्थी नं. 1 का छोटा भाई है। अपीलार्थी नं. 1 का विवाह मृतक तुली शाह से हुआ था। शादी 24.02.2011 पर संपन्न हुई थी।

3. 19 सितंबर, 2011 को वास्तविक शिकायतकर्ता-उमा शंकर शाह (पीडब्लू-1) ने केतुग्राम पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जिसमें कहा गया कि उनकी भतीजी तुली शाह की शादी पिछले कुछ महीनों से अपीलार्थी नंबर 1 से हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि तुली शाह के माता-पिता का निधन तब हुआ जब वह बहुत कम उम्र की थी, उन्होंने ही तुली शाह की देखभाल की और उनका पालन-पोषण किया। शादी के समय तुली शाह के पति के परिवार को नकद और सोने के गहने दिए जाते थे। हालांकि, कुछ ही समय के भीतर, अपीलकर्ताओं ने अधिक दहेज के अभाव में मृतक को परेशान करना शुरू कर दिया। 4. अभियोजन पक्ष का मामला है कि 16 सितंबर, 2011 को मृतक ने अपने वैवाहिक घर में अपीलार्थियों द्वारा लगातार उत्पीड़न के कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी।

5. जाँच पूरा होने पर, ऊपर गिने गए अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, 304 बी और 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए। अभियुक्त व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। 6. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की और दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए।

7. अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने पर विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक स्थापित किया था और तदनुसार उन्हें दोषी ठहराया था।

8. याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा से असंतुष्ट होने के कारण उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को लागू करने के बारे में सोचा और तदनुसार अपील को खारिज कर दिया।

बुद्धदेव साहा और ओ. आर. एस. बनाम.

335

9. ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष हैं।

10. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि मृतक की अपीलार्थी संख्या 3 प्रतिमा साहा (सास) का इस अपील के लंबित रहने के दौरान निधन हो गया।

अपीलकर्ताओं के स्वयं के बारे में सुझाव:-

11. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को उस अपराध के लिए दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था। विद्वान वकील के अनुसार यह बिना किसी सबूत का मामला है।

उन्होंने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि अभियोजन पक्ष मौत का सही कारण स्थापित करने में सक्षम नहीं है। वह तर्क देंगे कि यदि अभियोजन पक्ष का मामला है कि मृतक ने लगातार उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की है, तो अभियोजन पक्ष को रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित करना होगा कि मौत का सही कारण क्या था।

12. विद्वान वकील ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के सही कारण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। 13. उन्होंने आगे कहा कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट भी विसरा में जहर के किसी भी निशान के बारे में चुप है। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील के अनुसार, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि मामला अप्राकृतिक मौत का है।

14. उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी पहले ही लगभग छह साल की सजा काट चुके हैं। वह प्रस्तुत करेगा कि इस समय यह मानते हुए कि दहेज के उद्देश्य से उत्पीड़न किया गया था, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता था, लेकिन किसी भी स्थिति में, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत नहीं।

15. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जाए और अपीलार्थियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाए।

पश्चिम बंगाल राज्य 336 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

राज्य के स्वयं के बारे में सुझाव:-

16. दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अविष्कार सिंघवी ने इस अपील का जोरदार विरोध किया है। वह प्रस्तुत करेंगे कि कानून की किसी भी त्रुटि की बात न करने में कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती है, यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थियों को उस अपराध के लिए दोषी ठहराने में निचली अदालतों द्वारा की गई थी जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था।

17. विद्वान वकील ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि शादी की तारीख से कुछ महीनों के भीतर, मृतक की संदिग्ध परिस्थितियों में उसके वैवाहिक घर में मृत्यु हो गई। उनके अनुसार, इस बात का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर भारी सबूत हैं कि दहेज के अभाव में सभी अपीलार्थियों द्वारा मृतक का लगातार उत्पीड़न किया गया था।

18. विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 113 बी की ओर आकर्षित किया, जो अभियुक्त के खिलाफ एक अनुमान लगाती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी इस प्रकार है:-

“धारा 113 ख। दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान।-- जब यह प्रश्न किया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, तो अदालत यह मान लेगी कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या की थी।”

19. विद्वान वकील ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए और 113 बी के बीच एक निश्चित अंतर बताया। धारा 113 ए में, विधानमंडल ने "मई" शब्द का उपयोग करने के बारे में सोचा है। इसलिए, तथ्यों के दिए गए समूह में, न्यायालय यह मान सकता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत इस्तेमाल किया गया शब्द "होगा" है। "होगा" शब्द को देखते हुए, न्यायालय के पास अनुमान लगाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।

20. वह प्रस्तुत करेंगे कि रिकॉर्ड पर आंतरिक सबूत हैं जो इंगित करते हैं कि मृतक की मृत्यु जहर के सेवन के कारण हुई थी। वह प्रस्तुत करेंगे कि पोस्टमॉर्टम के दौरान एकत्र किए गए विसरा के नमूने को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजने में लंबे समय से देरी हुई थी और शायद देरी के कारण, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में अभी तक विसरा में जहर के कोई निशान नहीं पाए गए हैं।

बुद्धदेब साहा और ओ. आर. एस. बनाम.

337

21. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील श्री अविष्कार सिंघवी ने प्रार्थना की कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जा सकता है।

22. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की है।

विश्लेषण

23. निर्विवाद रूप से, जहां तक मृत्यु के सही कारण का संबंध है, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। इस तथ्य से कोई बच नहीं सकता है कि विसरा रिपोर्ट में भी जहर के कोई निशान पाए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 24. तथापि, विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में मामले के उपरोक्त पहलू पर काफी संतोषजनक तरीके से चर्चा की है, जो निम्नानुसार है:-

“यह मोदी की राय है कि कुछ मामलों में, जिनमें जहर से मृत्यु के संकेत थे, रासायनिक परीक्षक किसी भी जहर का पता लगाने में विफल रहे और उस मामले में न्यायाधीश का कर्तव्य सबूतों, लक्षणों, पोस्टमॉर्टम उपस्थिति आदि का वजन करना है, ताकि न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा

सके। मोदी की यह भी राय थी कि अनुपयुक्त नमूने, गलत नमूना स्थल, भंडारण में देरी, विसरा की जांच में देरी, गलत विश्लेषणात्मक तकनीक का उपयोग उचित विश्लेषण को विफल या विकृत कर सकता है और अंतिम परिणाम गलत हो सकता है। मैंने इस संबंध में मोदी और एच. डब्ल्यू. वी. कॉक्स द्वारा की गई टिप्पणियों को देखा है। मैंने विभिन्न विषों और लक्षणों के संबंध में उनके द्वारा किए गए अवलोकनों को देखा है। जाँच रिपोर्ट (एक्स्ट-2) के अनुसार, पुलिस अधिकारी ने देखा था कि दाहिने नथुने से झाग निकल रहा था। पुलिस अधिकारी द्वारा नोट की गई त्वचा का रंग सफेद था। पोस्टमॉर्टम के दौरान यह देखा गया कि रिगोर मोर्टिस मौजूद नहीं थे, आंखें आधी बंद थीं, नाक और मुंह से झाग निकल रहा था। शरीर के खुलने पर ग्रासनली, फेफड़े, श्वासनली और ब्रॉन्कियल के पेड़ भीड़भाड़ वाले पाए गए। डॉक्टर को पेट में भोजन के कण और तीखी गंध के साथ फूड मिला। विभिन्न मामलों के विश्लेषण पर मोदी एंड कॉक्स ने लक्षणों से जहर का पता लगाने के लिए एक दिशानिर्देश तैयार किया था। उनके अनुसार, अफीम या उसके एल्कलॉइड के मामले में मुंह और नाक से सफेद झाग निकल सकता है। यह भी उनकी राय थी कि

पश्चिम बंगाल राज्य 338 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

पेट या फेफड़ों जैसे सभी आंतरिक अंगों में भीड़ हो सकती है। उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया है कि यदि पेट खोलने पर पता लगाने योग्य गंध मिल सकती है, तो वह ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिकों, अफीम, फॉर्मैल्डिहाइड आदि जैसे जहर के उत्सर्जित पदार्थ हो सकते हैं।

यहाँ, इस मामले में पोस्टमॉर्टम टिप्पणियों से पता चलता है कि यह निश्चित रूप से जहर के कारण मौत का मामला था। यह तथ्य है कि जहर की प्रकृति का पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन सभी लक्षण साबित करते हैं कि तुली की मृत्यु जहर के सेवन से हुई थी और उसकी मृत्यु का कोई अन्य संभावित कारण नहीं है। जाहिर है कि मौत सामान्य परिस्थितियों की तुलना में कहीं और हुई थी।”

(जोर दिया गया) 25। निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई उपरोक्त बातों पर उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले के पैराग्राफ 13 में विचार किया, जिस पर नीचे चर्चा की गई है:-

“अभियुक्त व्यक्तियों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को यह सुझाव देते हुए एक व्यर्थ याचिका दायर करने की मांग की कि तुली की मृत्यु बीमारी के कारण हुई, न कि जहर खाने से। इस दलील की पुष्टि किसी भी साक्ष्य से नहीं की जा सकी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को प्रदान करने का भार उस पर होता है। यह विवाद में नहीं है कि तुली की शादी 24 फरवरी, 2011 को अपीलार्थी नंबर 1 से हुई थी। इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है कि तुली की शादी के सात महीने के भीतर उसके वैवाहिक घर में मृत्यु हो गई थी। पीडब्लू-9 डॉ. एन. घटक के साक्ष्य से यह पता चलता है कि मृतक के विसरा के नमूने में कोई जहर नहीं मिला था जो 22 फरवरी, 2012 को प्राप्त हुआ था। पीडब्लू-10 चिकित्सा अधिकारी हैं जिन्होंने 17 सितंबर, 2011 को तुली के शव का पोस्टमॉर्टम किया था। इस गवाह ने अपने साक्ष्य में कहा कि आंतों की जांच में “पेट में तीखी गंध के साथ गंध सामग्री पाई गई थी”। पीडब्लू-10 ने कहा कि अगर

कोई जहर खाता है, तो इस तरह की तीखी गंध मिल सकती है।पीडब्लू-10 ने मृत्यु के कारण के बारे में कोई निर्णायक राय नहीं दी क्योंकि विसरा को रासायनिक जांच के लिए भेजा गया था। साक्ष्य के क्रम में पूछताछ किए जाने पर, पीडब्लू-10 ने स्वीकार किया कि यदि रासायनिक जांच के लिए विसरा का नमूना भेजने में देरी होती है, तो जहर 339 नहीं हो सकता है।

बुद्धदेब साहा और ओ. आर. एस. बनाम.

पाया गया।वर्तमान मामले में, विसरा 22 फरवरी, 2012 को रासायनिक जांच के लिए प्राप्त किया गया था, यानी पांच महीनों के बाद।यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उपरोक्त अवधि के दौरान विसरा के नमूने को ठीक से संरक्षित किया गया था।हालाँकि मृतक के विसरा के नमूने में कोई जहर नहीं पाया जा सका, लेकिन गवाहों के साक्ष्य और जाँच रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि तुली की मृत्यु "सामान्य परिस्थितियों से अलग" हुई थी।जाँच रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वास दिलाती है क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तुली की मृत्यु जहर खाने से हुई थी।जाँच के समय यह पता चला कि मृतक के मुँह और नाक से झाग निकल रहा था।"सामान्य परिस्थितियाँ" अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप से अर्थ है प्राकृतिक मृत्यु। दूसरे शब्दों में, "सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अन्यथा" अभिव्यक्ति का अर्थ है मृत्यु सामान्य क्रम में नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से संदिग्ध परिस्थितियों में होना।2013 (4) अपराध 480 (उच्चतम न्यायालय) में मध्य प्रदेश के भूपेंद्र बनाम राज्य के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि दहेज मृत्यु के प्रत्येक मामले में विसरा की रासायनिक जांच अनिवार्य नहीं है।आई. पी. सी. की धारा 304 बी के उद्देश्य के लिए केवल एक अप्राकृतिक मृत्यु का तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत एक अनुमान को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। भूपेंद्र के मामले (ऊपर) में फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ 26 को नीचे उद्धृत किया गया है:

“26. इन निर्णयों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दहेज मृत्यु के प्रत्येक मामले में विसरा की रासायनिक जांच अनिवार्य नहीं है; भले ही विसरा रिपोर्ट मांगी गई हो, इसकी अनुपस्थिति आवश्यक रूप से अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है जब आई. पी. सी. की धारा 304-बी या आई. पी. सी. की धारा 306 के तहत दंडनीय अप्राकृतिक मौत होती है; आई. पी. सी. की धारा 304-बी (साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-बी के तहत अनुमान के साथ पढ़ा जाता है) या आई. पी. सी. की धारा 306 (साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ए के तहत अनुमान के साथ पढ़ा जाता है) को आमंत्रित करने वाली अप्राकृतिक मौत के मामले में जब तक जहर का सबूत है, तब तक जहर की पहचान बिल्कुल आवश्यक नहीं हो सकती है।

पश्चिम बंगाल राज्य 340 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

हाथ में मामले की ओर लौटते हुए, अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तुली की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अलग हुई थी।”

(जोर दिया गया) 26। यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर आंतरिक साक्ष्य हैं कि हाथ में मामला जहर से आत्महत्या का है। पोस्टमॉर्टम करने वाले पीडब्लू-10 (मेडिकल ऑफिसर) ने बयान दिया है कि "पेट में तीखी गंध वाली गंध सामग्री पाई गई थी"। विशेषज्ञ ने कहा कि जहर के सेवन के मामलों में इस तरह की तीखी गंध पाई जाएगी। पीडब्लू-10 ने स्वीकार किया कि यदि रासायनिक परीक्षण के लिए विसरा के नमूने को आगे बढ़ाने में कोई देरी होती है, तो जहर का पता नहीं लगाया जा सकता है।

27. दुर्भाग्य से, हाथ में मामले में, एफएसएल को 22 फरवरी, 2012 को रासायनिक विश्लेषण के लिए विसरा प्राप्त हुआ था, जो लगभग पांच महीनों की अवधि के बाद है।

28. "नकारात्मक विसरा रिपोर्ट और इसके चिकित्सा-कानूनी पहलू" शीर्षक वाले एक शोध लेख में, यह उल्लेख किया गया है कि कई मामलों में, विसरा रिपोर्ट तीन प्रमुख आधारों पर नकारात्मक होती है, अर्थात् यह प्रक्रिया आधारित, नमूना आधारित या प्रयोगशाला आधारित हो सकती है। उक्त शोध पत्र से पता चलता है कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें विसरा परीक्षण निम्नलिखित परिस्थितियों में यौगिकों की उपस्थिति का खुलासा नहीं कर सकता है:—

1. एफ. एस. एल. द्वारा प्राप्त नमूना मात्रा इष्टतम विश्लेषण के लिए निर्धारित मात्रा की तुलना में बहुत कम है।

2. आवश्यक मात्रा और परिरक्षक की गुणवत्ता का उपयोग नमूने के दौरान नहीं किया जाता है;

3. नमूने के संरक्षण के लिए उचित तापमान, समय और पात्र का रखरखाव नहीं किया गया;

4. उल्टी, शुद्धिकरण या गुर्दे द्वारा प्रणाली से उन्मूलन या मृत्यु से तुरंत पहले अस्पताल में लंबे समय तक रहने के कारण जहर का पता लगाने में भिन्नता;

5. जांच के लिए विसरा के साथ पेट धोने (गैस्ट्रिक लैवेज) और उल्टी नहीं भेजना; 341

बुद्धदेब साहा और ओ. आर. एस. बनाम.

6. कुछ जैविक जहर अनुचित संरक्षण या तापमान नियंत्रण के कारण विघटित हो जाते हैं।

7. शरीर पर नमूना संग्रह का स्थान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 8. पोस्टमॉर्टम अपघटन में, ऊतक में मौजूद कई जहर रासायनिक परिवर्तनों से गुजरते हैं जिनका नियमित विषाक्त विश्लेषण में पता नहीं लगाया जा सकता है।

29. यह न्यायालय महाबीर मंडल बनाम बिहार राज्य, (1972) 1 एस. सी. सी.

748, मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी (सत्रहवें संस्करण) के पृष्ठ 477 पर पाए गए अवलोकनों को देखा और कहा कि कुछ परिस्थितियों में, यदि पूरा जहर वाष्पीकरण द्वारा फेफड़ों से गायब हो गया है, या उल्टी और शुद्धिकरण द्वारा पेट और आंतों से हटा दिया गया है, और

अवशोषण के बाद डिटॉक्सिफाई एड, संयुग्मित और गुर्दे और अन्य चैनलों द्वारा प्रणाली से समाप्त कर दिया गया है, तो यह संभव है कि जहर के निशान न हों।

30. इस प्रकार, केवल विसरा रिपोर्ट में जहर का पता नहीं चलने को इस तथ्य के निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि पीड़ित की मौत जहर से नहीं हुई है।

31. महाबीर मंडल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कार्य किया है:-

“रासायनिक परीक्षक की 23 दिसंबर, 1963 की रिपोर्ट के लिए Mr.Chari द्वारा खाली संदर्भ दिया गया है, जिसके अनुसार इंदिरा मृतक के विसरा में कोई जहर नहीं पाया जा सका है। यह परिस्थिति, हमारी राय में, इस निष्कर्ष के खिलाफ नहीं होगी कि मृतक की मृत्यु जहर के कारण हुई थी। विशेष रूप से सिंथेटिक हाइपोटिक्स और वनस्पति एल्कलॉइड समूहों के कई जहर हैं, जो कोई विशिष्ट संकेत नहीं छोड़ते हैं जैसा कि पोस्टमॉर्टम परीक्षा में देखा जा सकता है।”

(जोर दिया गया) 32। इस न्यायालय का उपरोक्त अवलोकन मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी में दिए गए संदर्भ पर आधारित था। उन संदर्भों को इस न्यायालय द्वारा भी संदर्भित किया गया था, जो इस प्रकार हैं:-

“यह बहुत संभव है कि एक व्यक्ति जहर के मल से मर सकता है, और फिर भी मृत्यु के बाद शरीर में कोई नहीं पाया जा सकता है, अगर पूरा

पश्चिम बंगाल राज्य 342 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

वाष्पीकरण द्वारा फेफड़ों से जहर गायब हो गया है, या उल्टी और शुद्धिकरण द्वारा पेट और आंतों से हटा दिया गया है, और अवशोषण के बाद डिटॉक्सिफाई किया गया है, गुर्दे और अन्य चैनलों द्वारा सिस्टम से संयुग्मित और समाप्त किया गया है। कुछ वनस्पति विषों का विसरा में पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास कोई विश्वसनीय परीक्षण नहीं है, जबकि कुछ कार्बनिक विष, विशेष रूप से एल्कलॉइड और ग्लूकोसाइड, जीवन के दौरान ऑक्सीकरण हो सकते हैं या मृत्यु के बाद सड़ने से, अन्य पदार्थों में विभाजित हो सकते हैं जिनकी कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं होती है जो उनकी पहचान के लिए पर्याप्त होती है।”

(जोर दिया गया) 33। जैसा कि इस न्यायालय ने कई मामलों में बताया है, जहां मृतक की मौत जहर के परिणामस्वरूप होती है, जहर को सफलतापूर्वक अलग करना और इसे पहचानना मुश्किल है। यदि अन्य परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध को इंगित करती हैं, तो इस संबंध में सकारात्मक साक्ष्य की कमी के परिणामस्वरूप पूरे अभियोजन मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है।

34. मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी के 23 वें संस्करण के अनुसार, संपादक: के. मथोरन और अमृत के. पटनायक, संरक्षित सामग्री को संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से संबंधित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में जल्द से जल्द भेजा जाना चाहिए। अन्यथा, विषाणु के विश्लेषण के दौरान विष का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही उनमें कुछ विष हो।

35. केन कुलिग एम. डी. ने क्रिटिकल केयर सीक्रेट्स (चौथा संस्करण), 2007 में कहा है कि पेट से दवाओं को हटाने में पूरी तरह से प्रभावी होने के लिए अंतर्ग्रहण के तुरंत बाद गैस्ट्रिक लैवेज किया जाना चाहिए। इस कारण से, कई चिकित्सक उन रोगियों को शौच नहीं करते हैं जिन्होंने ओवरडोज किया है यदि अंतर्ग्रहण के बाद से 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका है।

36. हम इस कानूनी प्रस्ताव से अवगत हैं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले से निपटने के दौरान, न्यायालय को चौकस रहना होगा। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सावधानी बरतने का निर्देश दिया था। [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 74] आर. बनाम से उद्धृत (ए. आई. आर. पी. 89 पैरा 60) हॉज [(1838) 2 लॉ सी. सी. 227]।

“मन एक दूसरे के लिए परिस्थितियों को अनुकूलित करने में आनंद लेने के लिए उपयुक्त था, और यहां तक कि उन्हें थोड़ा तनाव देने में, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें एक जुड़े हुए पूरे के हिस्से बनाने के लिए मजबूर करने के लिए; और अधिक सरल 343

बुद्धदेब साहा और ओ. आर. एस. बनाम. पश्चिम बंगाल राज्य

व्यक्ति का मन, इस तरह के मामले पर विचार करते हुए, खुद को ओवररीच और गुमराह करने की अधिक संभावना रखता था, कुछ छोटी सी कड़ी प्रदान करने के लिए जो वांछित है, अपने पिछले सिद्धांतों के अनुरूप कुछ तथ्य को हल्के में लेने के लिए और उन्हें पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक था।”

37. इस प्रकार, न्यायालय को अनजाने में उसी खतरनाक जाल में नहीं फंसना चाहिए जिससे बचने के लिए संविधान पीठ ने आगाह किया है। 38. अभिलेख पर समग्र साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम यह विचार रखना चाहते हैं कि किसी भी सकारात्मक विसरा रिपोर्ट के अभाव में, अभियोजन पक्ष अपने मामले को स्थापित करने में विफल रहा है।

39. पूर्वगामी कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

40. परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। 41. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन